CEASI TIMES

14th July 2025

HINDI

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्क्फोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क् का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- **15+ राज्य**
- **15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया**
- **20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया**
- **5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया**
- **3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया**
- **30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया**

बिहार में 267 नए कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) से छोटे किसानों को मिलेंगी मशीन

बिहार सरकार इस वित्तीय वर्ष में 267 नए कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित करने जा रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें किराये पर मिल सकें। हर नया CHC एक अलग पंचायत में बनाया जाएगा, जिससे राज्य की सभी 8,093 पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य और नजदीक आएगा। अभी तक 950 सेंटर पहले ही चालू हो चुके हैं। यह पहल खासकर सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। हर CHC पर कम से कम एक मुख्य मशीन—जैसे टिलर, सीडर, ट्रांसप्लांटर, हार्वेस्टर या थ्रेशर—उपलब्ध होगी।

प्रत्येक सेंटर की लागत लगभग ₹10 लाख तक होती है, जिसमें सरकार सब्सिडी देकर किसानों की लागत को कम करती है। 35 बीएचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए ₹1.6 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि अन्य उपकरणों पर 40% सब्सिडी—अधिकतम ₹4 लाख तक—प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह (SHGs), जीविका समूह, क्रॉप क्लस्टर फेडरेशन, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) जैसे ग्रामीण हितधारकों को मिलेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच मिल सकेगी

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा और सब्सिडी तक आसान पहुंचः कृषि स

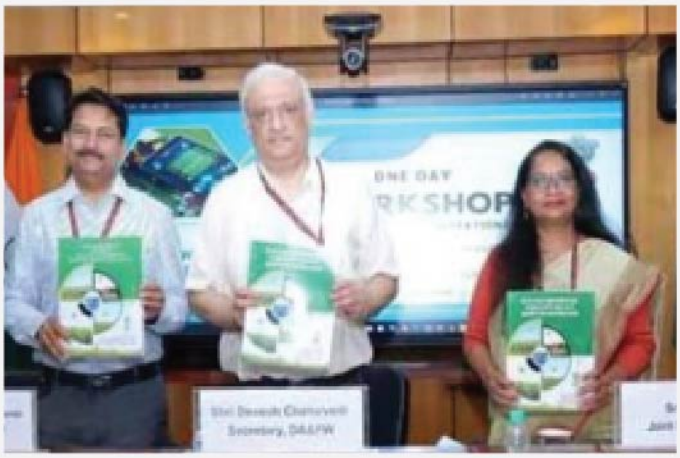

कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्लेटफॉर्म 2.0 और 'नमो ड्रोन दीदी' पोर्टल जैसे डिजिटल सिस्टम भारत में कृषि यंत्रीकरण को नया रूप दे रहे हैं। यह कार्यशाला कृषि मंत्रालय के यंत्रीकरण एवं तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें दिखाया गया कि ये प्लेटफॉर्म कैसे पारदर्शिता बढ़ाते हैं, कामकाज में गति लाते हैं, और कृषि मशीनों पर सब्सिडी से जुड़ी पुरानी समस्याओं को हल करते हैं। कार्यशाला में फसलों के अनुसार ड्रोन से खाद एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) भी लॉन्च की गईं।

'नमो ड्रोन दीदी योजना' इस कार्यक्रम की मुख्य झलक रही, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव जैसे कार्यों में सक्षम बनाया जा रहा है। नया ड्रोन पोर्टल राज्यों को ड्रोन संचालन की निगरानी, प्रमाणन प्रबंधन और उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड उपलब्ध कराता है। लाइव डेमो और खुली चर्चाओं के माध्यम से राज्यों के अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। ये डिजिटल उपकरण सब्सिडी तक पहुंच को सरल बनाएंगे, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देंगे और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यंत्रीकरण को और अधिक समावेशी बना

स्मार्ट खेती और जलवायु लचीलापन के लिए गूगल ने लॉन्च किए AI टूल्स

गूगल ने भारत में डेटा-आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कई नई पहलें शुरू की हैं, जिनमें 'एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन (AMED)' API शामिल है। यह टूल पूरे भारत में फसलों और खेतों की गतिविधियों की रीयल-टाइम जानकारी देता है, जिससे किसान और अन्य हितधारक सटीक खेती (precision farming) से जुड़े समाधान विकसित कर सकते हैं जो उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के जोखिम को कम करने में मदद करें। यह प्लेटफॉर्म गूगल के 'एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग (ALU)' सिस्टम पर आधारित है और इसका उद्देश्य खेती से जुड़े फैसलों को सामान्य जानकारी से हटाकर बारीकी से विश्लेषण और कार्रवाई योग्य डेटा पर आधारित बनाना है।

IIT-खड़गपुर के साथ मिलकर Google DeepMind 'Amplify Initiative' के तहत स्थानीय डेटा सेट तैयार कर रहा है ताकि AI टूल्स को भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के अनुरूप बनाया जा सके। गूगल के डॉ. मनीष गुप्ता ने कहा, "हम मूल AI को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान में बदल रहे हैं।" खेती में AI के इस्तेमाल से स्मार्ट यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, इनपुट उपयोग का अनुकूलन होगा, और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों से निपटने की क्षमता मजबूत ह

मेरठ में एग्रीटेक हब से स्मार्ट खेती और ग्रामीण नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SVPUAT) में एक नया एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप शोकेस केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और जयंत चौधरी द्वारा उद्घाटित किया गया। यह पहल सटीक खेती (precision farming) और ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT रोपड़ के सहयोग से स्थापित यह हब IoT सेंसर, स्मार्ट सिंचाई, ऑटोमेशन और रीयल-टाइम डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को जोड़कर टिकाऊ और डेटा-आधारित कृषि को प्रोत्साहित करेगा। यह हब किसानों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाकर क्षेत्रीय, व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए एक साझेदारी मंच के रूप में कार्य करेगा।

इस पहल में कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और एक मॉडल स्मार्ट फार्म की व्यवस्था भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान SVPUAT और IIT रोपड़ के बीच एक समझौता (MoU) भी हुआ और 20 एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए। IIT रोपड़ ₹75 लाख की तकनीकी सहायता, IoT, AI और साइबर-फिजिकल सिस्टम्स के माध्यम से इस हब को सहयोग देगा। यह हब छोटे किसानों को आधुनिक उपकरणों और ज्ञान से सशक्त करेगा और ग्रामीण युवाओं को एग्री-उद्यमिता की ओर प्रेरित करेगा। यह पहल स्मार्ट यंत्रीकरण और समावेशी नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा देग

तेज़ी से उभर रहा है आंध्र प्रदेश, बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्

आंध्र प्रदेश ने बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जहाँ उत्पादन 275.13 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है और लगभग 15.98 लाख हेक्टेयर भूमि पर विविध फसलें उगाई जा रही हैं। राज्य तेजी से भारत के प्रमुख बागवानी केंद्रों में से एक बनता जा रहा है, जहाँ मिर्च, कोको, नींबू, ऑयल पाम, पपीता, टमाटर, काजू, आम, केला और संतरा जैसी फसलें विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा रही हैं।

कृष्णा ज़िले के अटकूर में आयोजित डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह के दौरान बताया गया कि भारत वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन रहा है। वर्ष 2024–25 में खाद्यान्न उत्पादन 354 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन से यह स्पष्ट होता है कि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं। समारोह में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों को भी सम्मानित किया गया और विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

कोलार का ऐतिहासिक कटहल बाग बना नवाचार का केंद

कर्नाटक का पहला कटहल प्रोजेनी ऑर्चर्ड, कोलार के पास तमका गांव स्थित उद्यानिकी कॉलेज परिसर में विकसित किया गया है, जो अब नवाचार और जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र बनता जा रहा है। कोलार शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित यह विशेष बागान वर्षों की समर्पित खेती और संरक्षण प्रयासों का प्रतिफल है, जहाँ परिपक्व कटहल के वृक्ष दोनों ओर कतार में खड़े होकर एक विशिष्ट प्राकृतिक छटा प्रस्तुत करते हैं।

यह परिसर केवल एक शैक्षणिक स्थान नहीं, बल्कि कटहल की खेती, अनुसंधान और मूल्यवर्धन का जीवंत प्रयोगशाला बन चुका है। यहां की समृद्ध जैविक विविधता और नवाचार पर निरंतर फोकस ने कटहल को एक पोषणयुक्त और व्यावसायिक रूप से लाभकारी फल के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया है। यह बाग कर्नाटक की स्थानीय उद्यानिकी विरासत को संरक्षित रखने के साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों से सामंजस्य बिठाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

दुबई पहुँचे मेघालय के ऑर्गेनिक अनानास, वैश्विक बाजार में बढ़ा राज्य का हॉर्टिकल्चर प्रभाव

मेघालय ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहाँ री-भोई जिले के जिरांग ऑर्गेनिक्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से प्राप्त प्रीमियम ऑर्गेनिक अनानास की 2 मीट्रिक टन खेप दुबई भेजी गई। यह निर्यात IFAD समर्थित मेघा-लैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की वैश्विक बागवानी मूल्य श्रृंखला में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। यह पहल न केवल जैविक खेती को बढ़ावा देती है, बल्कि टिकाऊ कृषि व्यापार मॉडल को भी मजबूत करती है।

इस अवसर पर स्थानीय उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिला, जहाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कई क्षेत्रों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनमें खेती, बेकरी, प्रिंटिंग, कैफे और होमस्टे जैसे विविध क्षेत्रों के नवप्रवर्तनकारी शामिल थे। यह पहल राज्य के समावेशी आर्थिक विकास और नवाचार को गति देती है। साथ ही, नई संस्थागत परियोजनाओं की घोषणाओं ने मेघालय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित किया है।

ओडिशा में शहरी घरों और छत बागवानी को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता अभियान शुरू

ओडिशा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में छत और घरेलू बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह पहल राज्य योजना योजना - शहरी बागवानी को बढ़ावा देने हेतु नवाचार परियोजनाएं के अंतर्गत चिह्नित की गई है और इसका क्रियान्वयन भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय बागवानी प्रयोगात्मक केंद्र (ICAR-IIHR) द्वारा किया जा रहा है। अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार प्रचार वाहन को पांच प्रमुख शहरों—भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बेरहामपुर और जयपुर—में जागरूकता प्रसार हेतु रवाना किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण घटते हरित क्षेत्रों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जो शहरी हीट द्वीप प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। प्रचार वाहन में ओड़िया और अंग्रेज़ी में दृश्य-श्रव्य सामग्री, तकनीकी प्रदर्शन, पर्चों का वितरण और नागरिकों से संवाद के लिए विशेषज्ञ सहायता केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अभियान सौंदर्य, पोषण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शहरी व उप-शहरी बागवानी को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों, संस्थानों और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है।

गोवा में डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए फ्राइस्वाल नस्ल को बढ़ावा

गोवा के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग (AHVS) राज्य के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए फ्राइस्वाल गायों की नस्ल को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में सत्तारी के कोपर्डेम स्थित पशु प्रजनन फार्म में लगभग 90 फ्राइस्वाल गायें रखी गई हैं।

यह क्रॉसब्रीड नस्ल — 5/8 होल्स्टीन फ्रिज़ियन और 3/8 साहीवाल — को 1987 में ICAR-CIRC मेरठ और रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। यह गायें प्रति 300-दिवसीय दुग्धावधि में लगभग 4,000 किलोग्राम दूध देती हैं, जिसमें 4% वसा होती है।

साहीवाल नस्ल के गुण गर्मी सहनशीलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि होल्स्टीन फ्रिज़ियन उच्च दूध उत्पादन में सहायक होती है, जिससे यह नस्ल गोवा की जलवायु के लिए उपयुक्त बनती है।

AHVS निदेशक वीणा कुमार ने ICAR के साथ सहयोग कर पूरे राज्य में इस नस्ल के उत्पादन और वितरण को बढ़ाने की इच्छा जताई। हाल ही में ICAR गोवा द्वारा आयोजित एक इंटरफेस मीटिंग में फ्राइस्वाल जर्मप्लाज्म के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई।

ICAR गोवा के निदेशक प्रो. परवीन कुमार ने राज्य के पशुधन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

पशुपालकों के लिए वर्चुअल जागरूकता अभियान : पश्चिम और दक्षिण भारत में 1 लाख से अधिक लाभार्थी

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा 11 जुलाई 2025 को कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालकों के लिए एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पशुपालकों को नस्ल सुधार, समय पर टीकाकरण, जूनोटिक रोग नियंत्रण, और स्वच्छता जैसे प्रमुख विषयों पर जागरूक करना था।

यह कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा एवं नगर हवेली के 2,000 से अधिक CSC केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिससे 1 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए।

सत्रों में विशेषज्ञों के व्याख्यान और शैक्षिक वीडियो प्रस्तुत किए गए, जिनमें सेक्स-सॉर्टेड सीमेन (SSS) तकनीक और टीकाकरण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने आधुनिक पशुपालन तकनीकों के माध्यम से रोग रोकथाम और उत्पादन वृद्धि के लाभ बताए।

यह डिजिटल पहल DAHD की तकनीक-सक्षम "लैब से खेत तक" रणनीति को आगे बढ़ाते हुए भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जम्मू में पशुपालन योजनाओं की समीक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और कार्यकुशलता पर जोर

कृषि उत्पादन विभाग (APD) के प्रमुख सचिव शैलेन्द्र कुमार ने जम्मू के तलाब तिल्लो स्थित पशुपालन निदेशालय में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य जम्मू संभाग में पशुपालन से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था।

इस बैठक में संभाग के सभी जिलों के निदेशक, संयुक्त निदेशक, और मुख्य पशुपालन अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा में CAPEX, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP), केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (CSS), और नाबार्ड वित्तपोषित परियोजनाएं शामिल रहीं।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की प्रगति रही। बैठक में एफएमडी टीकाकरण, दुग्ध और कुक्कुट विकास, एवं कोल्ड-चेन अवसंरचना की जिलेवार स्थिति प्रस्तुत की गई।

किसान साथी पोर्टल और आउटपुट ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से विभाग द्वारा अपनाई गई डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली को पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

अधिकारियों को डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन में मूल्य संवर्धन, बाजार से जुड़ाव को मजबूत करने, और पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए 90% से अधिक बजटीय व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी पशुधन विकास को दी गति

उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में "भारत में पशु नस्लों का विकास" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की पशुधन विकास और स्वदेशी नस्ल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया गया।

इस अवसर पर अमेठी, बरेली और मथुरा में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, साथ ही गोरखपुर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन भी किया गया।

कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण में पशुधन की अहम भूमिका पर चर्चा की गई, विशेषकर नस्ल सुधार और वैज्ञानिक प्रजनन विधियों पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश, जो देश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, मुंह एवं खुर रोग (FMD) मुक्त पशुधन अभियान के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे रहा है।

राज्य स्थानीय पशु नस्लों के संरक्षण और डेयरी उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है। झांसी, गोरखपुर और काशी जैसे क्षेत्रों में महिला नेतृत्व वाली दुग्ध सहकारी समितियाँ आर्थिक सशक्तिकरण और नस्ल सुधार को आगे बढ़ा रही हैं।

इसके साथ ही, गौशाला योजनाएं, स्वामित्व आधारित पशु वितरण, और पोषण सहायता कार्यक्रम जैसे कल्याणकारी प्रयास ग्रामीण विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में ओडिशा को कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान

9 जुलाई को नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में ओडिशा को कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान राज्य की सतत कृषि विकास और किसान सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को मान्यता देता है।

यह पुरस्कार ओडिशा सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री एवं कृषि तथा किसान सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने प्राप्त किया। राज्य लौटने के पश्चात उन्होंने यह पुरस्कार एक संक्षिप्त समारोह के दौरान राज्यपाल गणेशी लाल को औपचारिक रूप से सौंपा। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार पडही भी उपस्थित रहे।

इस सम्मान से राज्य की कृषि व्यवस्था में जुड़े किसानों और हितधारकों को नई प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल ने ओडिशा के किसानों और अधिकारियों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में कृषक समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह पुरस्कार सतत कृषि पद्धतियों और ग्रामीण विकास में ओडिशा की अग्रणी भूमिका को और भी सुदृढ़ करता है।

राज्यवार और फसलवार कार्य योजनाओं से कृषि सुधार को मिलेगी नई दिशा

भारत में कृषि को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्यवार और फसलवार कार्य योजनाएँ तैयार की जाएंगी। विभिन्न प्रमुख फसलों पर केंद्रित बैठकें शुरू हो चुकी हैं—जिसमें हाल ही में सोयाबीन पर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में कपास और गन्ने जैसी फसलों पर विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य कपास मिशन जैसे कार्यक्रमों को अधिक परिणामोन्मुख और क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं पर आधारित बनाना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 96वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा की गई, वित्तीय प्रतिवेदन को अपनाया गया और नई प्रकाशन सामग्रियाँ जारी की गईं। बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया गया, साथ ही किसानों की वास्तविक ज़रूरतों पर आधारित मांग-आधारित अनुसंधान को प्राथमिकता देने की बात कही गई। "फसल औषधि केंद्र" जैसी नई अवधारणाओं पर भी चर्चा हुई, ताकि योजनाएँ ज़मीनी स्तर पर अधिक

तेलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार रणनीति तैयार करेगा भारत

भारत अब तेलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यवार और फसल-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह पहल जलवायु अनुकूलता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार मांग-आधारित अनुसंधान को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में सोयाबीन पर एक फसल-विशेष बैठक आयोजित की गई है, और आगामी दिनों में कपास, गन्ना तथा अन्य फसलों पर भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस समाधान तय किए जा सकें।

इसके साथ ही निम्न गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम लाने की तैयारी है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि यंत्रों के आधुनिकीकरण और नवाचार पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करें, प्रभावी योजनाओं को जारी रखें और अप्रासंगिक योजनाओं को बंद करें। यह पहल केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ व्यावहारिक और क्षेत्र-विशिष्ट कृषि नीति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

महाराष्ट्र सरकार कृषि श्रमिकों के लिए शुरू करेगी सामाजिक सुरक्षा योज

महाराष्ट्र सरकार जल्द ही कृषि श्रमिकों के लिए एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य किसान कल्याण को मजबूत करना और कृषि संकट को कम करना है। कृषि राज्य मंत्री श्री अशीष जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि सरकार का व्यापक लक्ष्य किसान आत्महत्याओं को शून्य तक लाना है। अब तक ₹69,000 करोड़ से अधिक की राशि किसान हितैषी योजनाओं पर खर्च की जा चुकी है, जिनमें नामो शेतकरी सम्मान योजना, फसल बीमा, कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम और मुआवज़ा अनुदान शामिल हैं। केवल नामो शेतकरी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में ₹56,000 करोड़ से अधिक वितरित किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए सरकार ₹5,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिसकी लागत में बचत ₹1 फसल बीमा योजना से हुई है। इसके अलावा, ₹500 करोड़ की AI आधारित कीट नियंत्रण नीति, उपग्रह आधारित नुकसान का तेज आकलन और 45,000 किलोमीटर धान सड़क निर्माण जैसी पहलें भी की जाएंगी। जैविक खेती, निर्यात-उन्मुख फसलें, और वन्यजीवों या प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए सहायता भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती को बढ़ावा देता 'सभ्वत मिठास' पहल

'सभ्वत मिठास' पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया और UPL SAS लिमिटेड मिलकर अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु-स्थायी खेती के तरीकों की जानकारी देकर उनकी उपज बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

अब तक 415 किसानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिससे यह समझने में मदद मिली कि वे अभी कौन-से तरीके अपना रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। किसानों को व्यावहारिक रूप से सीखाने के लिए प्रदर्शन प्लॉट भी तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ जल प्रबंधन, मिट्टी की सेहत सुधारने और जैविक खाद के उपयोग जैसी अच्छी खेती की विधियाँ दिखाई जा रही हैं।

किसानों को जोड़ने और जानकारी साझा करने के लिए कुल 46 बैठकें आयोजित की गई हैं — जिनमें 44 अनौपचारिक बैठकें, 2 औपचारिक बैठकें और 4 फील्ड डे शामिल हैं। इन आयोजनों में किसान आपस में अनुभव बाँटते हैं, विशेषज्ञों से सवाल पूछते हैं और टिकाऊ खेती को अपने सामने होते हुए देखते हैं।

इस तरह सर्वेक्षण, संवाद और प्रदर्शन के माध्यम से यह पहल किसानों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए बेहतर उपज लेने की प्रेरणा दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि अयोध्या क्षेत्र की खेती को लंबे समय तक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है

MODEL PLOT

CONTROL PLOT

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india